

कृषि व्यापार को बढ़ावा देगा ईसीटीए

प्रासंगिकता: जीएस -2: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिसमें भारत शामिल है और / या भारत के हितों को प्रभावित करता है।

की वर्ड्स : ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, टैरिफ उन्मूलन, टैरिफ में कमी, टैरिफ-दर कोटा, संवेदनशील उत्पाद, शून्य शुल्क पहुंच।

चर्चा में क्यों?

- अप्रैल-नवंबर के डीजीसीआईएस आंकड़ों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया 18,902.62 मिलियन डॉलर के कुल व्यापार के साथ भारत का 10 वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- इसी तरह, भारत, ऑस्ट्रेलिया का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं एकदूसरे के अत्यधिक पूरक हैं और इससे बहुत लाभ होगा क्योंकि ईसीटीए व्यवसायों के लिए व्यापार विविधीकरण के लिए नए अवसर खोला है।



ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए):

- यह एक महत्वपूर्ण कदम है और इसने कई क्षेत्रों में निर्यातकों और सेवा आपूर्तिकर्ताओं के लिए नए बाजार खोले हैं।
- ईसीटीए भारतीय उद्योग के तकनीकी उन्नयन और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के माध्यम से इष्टतम लाभों का उपयोग करके विकसित देशों के समर्थन से भारत के व्यापार को बढ़ावा देगा।
- भारत के लिए टैरिफ उन्मूलन:
 - इस समझौते के तहत, भारत को दो चरणों में एक आयातक देश द्वारा 100 प्रतिशत टैरिफ उन्मूलन प्रदान किया जा रहा है –
 - 983 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर तत्काल शून्य शुल्क, जो हमारे निर्यात के मूल्य का 964 प्रतिशत है और
 - शेष 113 टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है, जो टैरिफ लाइनों का 1.7 प्रतिशत है और पांच वर्षों में भारत के निर्यात का 3.6 प्रतिशत (मूल्य के संदर्भ में) है, जिससे शेष उत्पादों को लाभ होगा।
- **ऑस्ट्रेलियाई उत्पादों के लिए:**
 - भारत ज्यादातर कच्चे माल और मध्यवर्ती पर टैरिफ उन्मूलन के रूप में रियायतें दे रहा है, (टैरिफ-दर कोटा (टीआरक्यू) के साथ या उसके बिना टैरिफ कटौती (टीआर) के रूप में)
 - केवल कुछ कृषि उत्पादों जैसे संतरे, मंदारिन, बादाम, नाशपाती और कपास को सीमित कोटा के साथ अनुमति दी गई है।
 - भारत ने अपनी टैरिफ लाइनों के 40.3 प्रतिशत पर, शून्य शुल्क पहुंच प्रदान की है और शेष 30 प्रतिशत, चरणबद्ध तरीके से 3, 5, 7 और 10 वर्षों की अवधि में प्रदान की जाएगी।
 - इसमें 125 प्रशुल्क लाइनें भी शामिल हैं जिनके शुल्क में कमी होगी न कि उन्मूलन।

संवेदनशील उत्पाद:

- भारत ने बिना किसी रियायत के कई संवेदनशील उत्पादों को बाहर रखा है।
- इनमें दूध और अन्य डेयरी उत्पाद, चना, अखरोट, पिस्ता नट्स, गेहूं, चावल, बाजरा, सेब, सूरजमुखी बीज का तेल, चीनी, खली, सोना, चांदी, प्लैटिनम, आभूषण, लौह अयस्क और अधिकांश चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।

- जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए समझौते के 12 महीनों के भीतर देशों के बीच जैविक समतुल्यता पर एक पारस्परिक मान्य समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- ईसीटीए में, 5 डॉलर और 15 डॉलर के आयात मूल्यों पर शराब की बोतलों के लिए नौ वर्षों में 150 प्रतिशत टैरिफ में 25 प्रतिशत और शराब के लिए भारतीय डब्ल्यूपीआई के आधार पर 75 प्रतिशत की कटौती ऑस्ट्रेलिया के लाभ के लिए होगी, जो दुनिया का छठा सबसे बड़ा उत्पादक और वाइन का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है।

प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र:

- प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में भी, कुछ चॉकलेट, नाश्ते के अनाज, पास्ता, जैतून का तेल, प्रोटीन केंद्रित, तैयार नट, कॉफी और चाय सहित खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए 50 प्रतिशत तक के टैरिफ को समाप्त कर दिया गया है।
- ऑस्ट्रेलिया के लिए भेड़ के मांस पर टैरिफ का 30 प्रतिशत उन्मूलन किया गया है और वर्तमान में, भारत न्यूजीलैंड से भेड़ के मांस का आयात करता है।
- यह संधि ऐसे सामानों को उत्पत्ति के कड़े नियमों के माध्यम से अनुमति नहीं देती है जो पर्याप्त प्रसंस्करण की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

कृषि उत्पाद:

- भारत के आग्रह के आधार पर, कई कृषि वस्तुओं को पूरी तरह से प्राप्त मानदंड लागू किये गये हैं।
- इसके अलावा, जहां भी अन्य नियमों का उपयोग किया गया है, वे मुख्य रूप से सबहेडिंग के स्तर पर टैरिफ वर्गीकरण में परिवर्तन और बिल्ड-अप फॉर्मूला का उपयोग करके न्यूनतम 35 प्रतिशत (या बिल्ड-डाउन फॉर्मूला का उपयोग करके 45 प्रतिशत) मूल्यवर्धन को बोर्ड पर मुफ्त में शामिल करते हैं।
- भारत बासमती चावल, मसाले, विविध प्रसंस्कृत वस्तुओं, प्रसंस्कृत फलों और रसों, अनाज की तैयारी, कॉफी, चाय, समुद्री उत्पाद, ग्वार गम, तिल के बीज, गैर-बासमती चावल आदि का निर्यात करता है।
- ऑस्ट्रेलिया को कुल निर्यात 2021 में 104.83 प्रतिशत बढ़ा, और अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान डॉलर के संदर्भ में कृषि निर्यात 14.43 प्रतिशत बढ़ा है।

कृषि व्यापार में समग्र लाभ:

- **टैरिफ में कटौती:**
 - समझौते में कृषि वस्तुओं पर टैरिफ को कम करने के प्रावधान शामिल हैं, जिससे दोनों देशों के किसानों के लिए एक दूसरे के साथ व्यापार करना आसान और अधिक लागत प्रभावी हो जाता है।
- **बेहतर बाजार पहुंच:**
 - यह समझौता व्यापार के लिए गैर-टैरिफ बाधाओं को हटा देता है, जैसे कि सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय, जो कृषि उत्पादों के लिए सीमाओं को पार करना आसान बनाते हैं।
- **निवेश में वृद्धि:**
 - यह समझौता कंपनियों के लिए एक-दूसरे के देशों में निवेश करना आसान बनाता है, जिससे कृषि क्षेत्र में निवेश प्रवाह में वृद्धि होती है।
 - इससे नए बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सकता है और मौजूदा कृषि व्यवसायों का विस्तार हो सकता है, जिससे कृषि व्यापार में वृद्धि होगी।
- **प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया:**
 - यह समझौता दोनों देशों के व्यवसायों के लिए कृषि क्षेत्र सहित वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करना आसान बनाता है।
 - इस बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता से कृषि वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार बढ़ सकता है।
- **बेहतर बाजार जानकारी:**
 - इस समझौते में बाजार की जानकारी और विश्लेषण पर सहयोग बढ़ाने के प्रावधान शामिल हैं, जो दोनों देशों के किसानों को बाजार के रुझानों को बेहतर ढंग से समझने और प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकते हैं।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी सहयोग:**
 - इस समझौते में कृषि के क्षेत्र सहित अनुसंधान और विकास पर सहयोग के प्रावधान शामिल हैं।
 - इससे नई प्रौद्योगिकियों का विकास हो सकता है जो दोनों देशों के किसानों को लाभान्वित कर सकते हैं,

जिससे उनके लिए एक-दूसरे के साथ व्यापार करना आसान और अधिक कुशल हो सकता है।

निष्कर्ष:

- भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीटीए दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे दोनों देशों में व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण लाभ होने की उम्मीद है।
- समझौते के कार्यान्वयन के लिए दोनों सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच निरंतर सहयोग और सहयोग की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी पूरी क्षमता का एहसास हो।

स्रोत: द हिंदू बीएल

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

Q. मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- a) मुक्त व्यापार समझौते केवल आयातित वस्तुओं पर टैरिफ को कम करते हैं।
- b) मुक्त व्यापार समझौते देशों के बीच व्यापार के लिए बाधाओं को बढ़ाते हैं।
- c) मुक्त व्यापार समझौते देशों के बीच व्यापार के लिए बाधाओं को कम करते हैं।
- d) मुक्त व्यापार समझौते केवल वस्तुओं पर लागू होते हैं, सेवाओं पर नहीं।

समाधान: (C)

- एक मुक्त व्यापार समझौता दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता है जो व्यापार के लिए बाधाओं को कम करता है, जैसे कि आयातित वस्तुओं पर टैरिफ, आयात की जा सकने वाली वस्तुओं की मात्रा पर कोटा, और अन्य व्यापार प्रतिबंध।
- इसका लक्ष्य व्यापार प्रवाह को बढ़ाना और वस्तुओं और सेवाओं के लिए सीमाओं को पार करना आसान बनाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- इस प्रकार, कथन C सही है और अन्य कथन गलत हैं।
- मुक्त व्यापार समझौते माल और सेवाओं दोनों के लिए टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं को कम कर सकते हैं, और उनका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को बढ़ाना नहीं है बल्कि उन्हें कम करना है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

Q. भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीटीए) ने दोनों देशों के बीच कृषि व्यापार में वृद्धि को कैसे प्रभावित किया है और समझौते के तहत कृषि व्यापार को और बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? चर्चा कीजिये।